and uphold also the principles of democracy, especially Parliamentary democracy. I appreciate your concern. So are we concerned about it. Let us hope our concern is strong enough to resolve this impasse. Thank you.

Re. successful heart transplantation surgery by Dr. P. Venugopal and his team at AIIMS

SYED SIBTEY RAZI (Uttar Pradesh): Madam, with your permission, I stand to compliment Dr. Venugopal and his team, who have been successful in doing transplantation surgery of a heart on a person, who was very seriously sick.

Madam, it is really a landmark surgery, in which India was lagging behind. It is a big success that the heart of a 35 year-old lady, after declaration of her brain-death, was removed and given to the donee. We are happy that the condition of the patient is stable and he is progressing well.

Madam, as you know, the first heart transplantation was done in the year 1967 in South Africa. Since then, our doctors were interested to do this sort of surgery. But due to certain lacunae in the difinition of 'brain death' is defined not possible. Recently, a law was adopted in which 'brain death' is defined categorically. I congratulate the Government on bringing such a law enabling the doctors to perform this surgery. In our country, about 300 cases which require heart transplantation come up every year before doctors. I think a very good beginning has been made now. The most important aspect, perhaps, of the matter is that the cost of the operation, compared to that in the United States, is less. In the United States, the operation would cost $ 100,000 to S 200,000 whereas in our country the cost of the operation has come to Rs. 40,000/- and the post-operative expenses will be about Rs. 40,000/-. That is, in Rs. 80,000/- this operation could be done.

Through you, Madam, I would like to send my congratulations to the team of doctors. I hope the patient will recover quickly and he will be able to work smoothly in future. I also hope that more milestones like this will be created by our doctors. Through you, Madam, I send my congratulations and compliments to the associates and whole team of Dr. Venugopal who have done this operation in the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.

Madam, I thank you very much for giving me this opportunity.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We all congratulate the team of doctors who performed this operation. We wish the recipient a complete recovery and a healthy life. We are happy that our scientists are not only doing research, but they have also been able to do, in India, all that the foreign countries do with much better equipment at their disposal. The whole House, I am sure, joins me.

There is one more thing. There is something one can always remember. That is, this gentleman will be carrying a woman's heart. I hope he will take care of it. They say men always carry women's heart. I do not know where. But here, he will be carrying the woman's heart in the true sense of it.

SPECIAL MENTIONS

Need to check growing vulgarity and violence in films

श्री रामगोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से एक ऐसे मसले की तरफ केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसने पूरे देश में और पूरे समाज में एक चारित्रिक संकट की स्थिति पैदा कर दी है और यह मसला हिन्दुस्तान की फिल्मों में बढ़ रही अश्लीलता और हिंसा की प्रवृत्ति का है। स्थिति अब ऐसी

हो गई है कि पहले तो जब हम यह टी वी. घरों में नहीं हुआ करते थे, टॉकीज या थियेटर्ज में लोग फिल्म देखने जाते थे तो कुछ लोगों को यह मालूम पड जाता था कि यह फिल्म कैसी है। इसको बच्चों के साथ देखा जा सकता है या नही और उनसे बचा जा सकता है। लेकिन टेलीविज़न जो हमारे बेडरूम तक पहुंच गया है इसमें ऐसी स्थिति हो गई है कि कोई भी, जिसमें जरा भी लज्जा और शील है, वह परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर फिल्मों को नहीं देख सकता। हिंसा के ऐसे नए-नए तरीके फिल्मों के जरिए लोगों के सामने आ रहे हैं कि चाहे जलगांव सैक्स स्कैंडल जैसी बातें हों, चाहे दिल्ली में बच्चों के अपहरण जैसी बातें हों, इन सब का स्रोत किस तरह से कार्य हों, यह फिल्मों के जरिए लोगों के सामने आ रहे हैं। इस तरह लोग अपराधों में संलग्न होते हैं और उसी तरह की प्रक्रिया अपनाते हैं। महोदया, मुझे नहीं मालूम कि फिल्म सेंसर बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं उनके पुत्र और पुत्रियां हैं या नहीं, लेकिन उनके माता-पिता जरूर होंगे यह मैं निश्चित तौर पर मानता हूं और यह लोग इस तरह की फिल्में पास कर देते हैं, यह बहुत ही चिंता का विषय है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट से मांग करना चाहूंगा कि फिल्म सेंसर बोर्ड से इन लोगों को तो तत्काल हटाया जाए जोकि फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं। जो फिल्में बनाते भी हैं और पास भी करते हैं। महोदया, जो चोरी करता हो उसी को अगर न्याय करने की इजाजत दे दी जाएगी तो वह किसको दण्ड देंगे? कभी-कभी तो लोग कहते हैं कि अगर टी०एन० सेशन ही फिल्म सेंसर बोर्ड के चेयरमैन हों तो कुछ सुधार हो सकता है। दूसरे मैं चाहूंगा कि इस फिल्म इंडस्ट्री को जहां से कि ये फिल्में बनकर आती हैं, उसे भी कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट की परिधि में लाया जाए ताकि जो इससे पीड़ित हो या जिसकी सेंटीमेंटस इजोर्ड हों, वह उसमें जा सके और न्याय पा सके। महोदया, आर्नोल्ड टायनबी एक ग्रंथ लिखा कि दुनिया की तमाम सभ्यतायें इसीलिए नष्ट हो गयीं और उनमें दो चीजें बची अल्कोहलिज्म और न्यूडिटी। मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि इन फिल्मों के जरिए ये दोनों चीजें हिन्दुस्तान में बढ़ रही हैं जोकि देश की सभ्यता और संस्कृति के लिए खतरा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सरकार को निर्देश दें कि इस संबंध में जरूर कार्यवाही हो। अब हम लोग केवल न्यूज सुनने के लिए तो टी०वी० खोल सकते हैं, लेकिन बच्चे बैठे हों तो कोई कार्यक्रम नहीं देख सकते। आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. It is a very serious matter and I am sure, somebody from the Government, will take note of it. Mr. Mukherjee, a very senior Minister, from the Government side is there. Some more Ministers are there. Smt. Margaret Alva is there They should convey to the Government the feelings of the Members.

श्रीमती वीना वर्मा (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, माननीय यादव जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि फिल्मों में बढ़ती हिंसा और नग्नता को रोका जाना चाहिए। यह हमारे समाज में वल्गैरिटी तो फैलाती ही हैं, लेकिन इससे आपराधिक मनोरंजन की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, उस पर अवश्य चैक लगाया जाना चाहिए। मैडम, कुछ समय पूर्व हमारे सूचना प्रसारण मंत्रीजी ने एक सभा में कहा था कि इस विषय को कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत लाया जाएगा। तो सरकार इस पर जल्द विचार करे कि किस तरह से "वल्गैरिटी एण्ड क्रिमिनलायजेशन इन फिल्म्स" और उनकी थीम्स का जो अपराधीकरण हो गया है और अपराध पर आधारित जो फिल्म बनती हैं, उन पर चैक लगाया जाए। साथ ही खास तौर से ऐसे गाने और डांसेस जिनमें कि वल्गैरिटी का एक पूरा उदाहरण होता है नमूना होता है उस पर भी चैक लगाया जाए। इस तरह

के गाने और डांसेस या पर्टिकुलर सोन को कंजमर्स प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत लाए जाने पर विचार किया जाना चाहिए।

महोदया कुछ समय पूर्व मद्रास हाय-कोर्ट ने एक फैसला दिया था और उसमें विजय शंकर नामक अपराधी को फांसी की सजा दी गयी थी। उसने छः हत्यायें एक साथ की थीं लेकिन उसने कोर्ट में अपना बयान देते हुए एक महत्वपूर्ण प्रश्न समाज के सामने रखा था कि मैं अकेला ही इन हत्याओं का जिम्मेदार नहीं हूं। उसने एक फिल्म का नाम लिया था और बताया था कि मुझे हत्या करने की प्रेरणा उस फिल्म को देखकर हुई थी। तो क्या ऐसी फिल्मों से जुड़े प्रोड्यूसर्स एक्टर्स और डायरेक्टर्स को कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता है क्योंकि वह भी इस सबके लिए पूरे तौर पर जिम्मेदार हैं। इस संबंध में भी विचार होना चाहिए।

महोदया तीसरी बात मैं सुझाव के तौर पर यह कहना चाहूंगी कि मनोरंजन चैनल खास तौर से मैट्रो चैनल जोकि मनोरंजन चैनल है उसको "पे चैनल" बनाने पर विचार किया जाना चाहिए जिससे कि इस तरह की बढ़ती हिंसा नग्नता के नाम पर जो चीप मनोरंजन हम मैट्रो चैनल के नाम से दे रहे हैं उसे भी "पे चैनल" बना दिया जाए ताकि जिसकी प्राथमिकता हो वह उसे ले अन्यथा न ले। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए।

श्रीमती वीणा वर्मा : बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैडम मैं चाहूंगी कि आपकी तरफ से भी कुछ डायरेक्टिव सरकार को जायें ताकि इस पर कुछ न कुछ चैक हो सके।

उपसभापति : आप ठीक कह रही हैं के सरकार पैसे खर्च न करके इस तरह की चीजें एक्सचेकर्स का पैसा होता है यह एक्सपेंसेस मीडिया है टेलीविजन तो मैट्रो चैनल पर मैं तो इसे देखती नहीं हूं इसलिए मुझे मालूम नहीं कि कौनसे चैनल पर आता है अगर मैट्रो चैनल पर यह आ रहा है और सरकार टैक्स-पेयर्स की मनी से लोगों को वल्गेरिटि दिखा रही है और इसके लिए आप आवाज उठा रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिसको पैसे देकर वल्गेरिटि देखना हो वह अपना जाने उसकी अपनी मर्जी है।...

श्रीमती वीणा वर्मा : सिनेमा में जाते हैं लोग पैसे देकर।

उपसभापति : और प्रधान मंत्री जी ने स्वयं इस बात के ऊपर कहा था मीटिंग उन्होंने बुलाई थी मैंने पढ़ा था। मैं समझती हूं कि इस देश की जो के सबसे ऊंचे स्तर पर मिनिस्टर्स का इजहार हुआ है इसके ऊपर चिन्ता कि जब प्रधान मंत्री जी खुद इस बात के ऊपर गौर कर रहे हैं तो जरूर और मुझे यकीन है कुछ न कुछ नतीजा निकलेगा।

SHRI ABDUSSAMAD SAMADANI (Kerala): Madam, I also want to speak on this matter.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please speak.

SHRI ABDUSSAMAD SAMADANI: Madam, this is a very serious problem that is brought to your notice. My humble suggestion at this juncture is that some arrangement must be made to educate the Censor Board people about the concept of art in administering things. I think, the real problem is lack of knowledge about the concept of art. Many people think that art is something vulgar. They are separating are from life. There, some education has to be given to these people. I am reminded of a couplet of Allama Iqbal:

ए अहले नजर जौके नजर खूब है लेकिन,
जो शै की हकीकत को न देखे वह नजर क्या ?

मकसूदे हुनर सोजे हयाते अबदी है,
ये इक नफस दो नफस, मिसले शरर क्या?
बे मोजजा दुनिया में उभरती नहीं कौमें,
जो जार्बेकलीमी नहीं रखती, वह नजर क्या ?

Real art is something revealing the realities of life. I do not know whether our Censor Board people, our television people are concerned about all these things. I request the Chair that some arrangement be made to educate the people about the concept of art. Thank you, Madam.

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुदीन अहमद) : इस मसले को कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत लाया जा सकता है या नहीं, इस मसले को हम देखेंगे। मैं हाऊस के सामने इतना ही कह सकता हूं कि यह बहुत अहम बात हाउस के सामने आई है, इसको हम जरूर एग्जामिन करवायेंगे और जो कुछ इसमें हो सकता है करने की कोशिश की जाएगी।

उपसभापति : शुक्रिया। यह सब लोगों का मंत्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने रिएक्ट किया। हो सकता है कि मसले की अहमियत को, उसकी गंभीरता को देखकर और उसके साथ साथ आपकी शेर-ओ-शायरी जी थी उसने वास्तव में हमारे जमीर को झंझोर दिया और मंत्री जी भी बोले कि ठीक बात है। अच्छी

Art can be beautiful. Art should be beautiful. Art is not vulger. Humour is not vulgar. But it is how people project it, how people depict it which is important. We do not have to show something vulgar to enjoy and it should not be through violence, violence on women or children, because what they show is violence, generally on children. We have seen everyday in the House Members expressing concern about abduction of children in Delhi. The people have imbibed this vulgarity and violence through this very strong medium.

Thank you, Mantriji, for giving your comments.

Shri Hariprasad.

SHRI SATISH PRADHAN (Maharashtra): Madam, there is no quorum in the House... (*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: What is it?

SHRI AJIT P. K. JOGI (Madhya Pradesh): There is nothing... (*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Hariprasad, your name is given. I will call you.

SHRI SATISH PRADHAN: Madam, what about quorum?

SHRI B. K. HARIPRASAD: It is quite okay, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You cannot say okay. It is for the Chair to decide that. When a Member raises the issue of quorum, I have to decide whether there is quorum or not.

SHRI B. K. HARIPRASAD: He is not serious. He is taking it back.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is not a question of statistics. Let us find out if there is quorum or not.

SHRI B. K. HARIPRASAD: Madam, I would like to draw the attention of the Government....

THE DEPUTY CHAIRMAN: We cannot function until there is quorum. Please sit down. Let there be quorum. What Mr. Pradhan has raised is a technical point. We are thankful to him because, after all, the House should be run in order. The House should not be run in disorder. When the Members stand up and obstruct the running of the House we say, "The House is not in order." When there are not enough Members, if a Member shakes the conscience of the Members who are not here then we have to listen to him.

SYED SIBTEY RAZI (Uttar Pradesh): Madam, I stand on a point of order. This question is raised off and on. The whole Opposition has boycotted the House. A major chunk of the Members is not attending the House. In such a situation, is it necessary to consider the question of quorum?

THE DEPUTY CHAIRMAN: The responsibility of quorum is on the Government. It is not on the Opposition.

SYED SIBTEY RAZI: It is all right. But we want your ruling.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Sibtey Razi, I think my calculation is correct. The Congress Party Members are more than 25.

SHRI P. UPENDRA: Madam, the rule is very clear. You cannot change the quorum every time, whether some people boycott the House or not, the quorum remains the same.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The responsibility of quorum is on the Government. I mean the ruling party. The ruling party has brought the quorum. So, there is no problem now. But we cannot change it because two Members are less. It is never done.

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : मैडम, सरकार को और कांग्रेस को चिंता नहीं है, एकमात्र सदस्य सतीश प्रधान जी, शिव सेना के हैं, उन्होंने यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है इसलिए मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूं ।

उपसभापति : इसका भी धन्यवाद कि वह खुद बैठकर कोरम पूरा कर रहे हैं ।

SHRI SURESH KALMADI (Maharashtra): The Opposition is not entering the House. But they are signing the register outside and they are claiming daily allowance.

THE DEPUTY CHAIRMAN: They are not. I cannot give any ruling on what is happening outside the House. I am not responsible for what is happening in the lobby.

SHRI SURESH KALMADI: But they should not claim the daily allowance.

श्री राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) : मैडम, ऐसा नहीं है, ऐसे कोई नहीं कर रहा है कि बायकाट कर रहे हैं, कलमाडी जी को गलत जानकारी मिली है ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is something else. Mr. Hariprasad, finally you speak.

Need to check hoarding and profiteering in coffee

SHRI B. K. HARIPRASAD (Karnataka): Madam, I would like to draw the attention of the Government to hoarding and profiteering, which has resulted in the steep hike in coffee prices, in coffee. The liberalisation of pooling system, which has left the domestic coffee market at the mercy of the market forces, has turned this cheerful drink bitter to swallow. Against an estimated crop of 2.25 lakh tonnes a year, the domestic consumption of coffee is estimated at 70,000 tonnes. Yet the coffee prices have shot up steeply in recent months. This is affecting very badly the middle class in the southern part of the country. The Coffee Board says that the price rise is due to the hike in the auction price in the last quarter owing to a shortfall in production. As far as the consumer is concerned, the recent policy change which is initiated, is a mockery. In the past the Board had to act as a saviour of the growers' lobby to safeguard their interest from the sluggish demand. Now it seems that the Board has to reverse its role by coming to the rescue of the consumers from the lobby of coffee-growers. It would be wrong to say that the growers have benefited from this situation as a substantial portion of the auction stock has been cornered by the exporters and the traders expecting a big demand in the export market. In the name of export earning the coffee trade has exploited the domestic market. The havoc caused by the market forces has been compounded further by big players buying of stocks in auction at high prices for the export market. The market intervention